Central assistance provided to private sector in U. P.

2667. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) total amount of Central financial assistance provided during the last five years to the private sector in Uttar Pradesh for major industrial ventures; and

(b) details of private sector which have been provided with such financial assistance and the amount of assistance provided in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Information is being collected and to extent available and permissible under the rules will be laid on the Table of the House.

Claim of apple leasing and industries regarding computer manpower development

2668. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's approval had been obtained by the Apple Leasing and Industries Limited before announcing their claim through newspaper advertisements recently that it is the only organisation in the Indian Corporate sector in the field of computer manpower development; and

(b) if not, whether Government propose to make an inquiry to verify authenticity of the claim so that the public is not misled by companies making undue claims; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) No Sir.

(b) Government does not agree with the claim made by the company. Specific approval of Government is not required for advertisements issued by any party. However, if any misleading statement is made, appropriate steps can be initiaterd against the party.

भ्रष्टाचार निरोधक अभियान के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

2669. **श्री सोहन लाल धूसिया :**
श्री जे०पी० गोयल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार निरोधक अभियान के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आला अफसरों के घरों और दफ्तरों में छापे मारे हैं और अनुचित तरीकों से धन कमाने, गोलमाल और धोखाधड़ी करने के लिए सैंतालीस व्यक्तियों के विरुद्ध 31 मुकदमे दर्ज किये हैं; जैसा कि इस संबंध में 25 फरवरी, 1987 के जनसत्ता में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) उक्त छापों में जिन श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गए हैं उनके नाम, पदनाम क्या हैं तथा वे इस समय कहां-कहां तैनात हैं; और

(ग) क्या उक्त छापों में जो व्यक्ति दोषी पाये गये हैं वे या तो पहले पकड़े गये थे या उनके यहां छापे तो पड़े थे किन्तु वे कानून की गिरफ्त में आने से बच गये थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आय के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्तियों रखने, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक कदाचार के आरोपों के बारे में दर्ज 31 मामलों की जांच के सिलसिले में 24-2-1987 को सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 36 अधिकारियों और

9 निजी व्यक्तियों/कम्पनियों के निवास स्थानों/कार्यालय परिसरों की तलाशी ली थी ।

(ख) इन मामलों में ग्रस्त समूह "क" और समूह "ख" के अधिकारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी	17
उपक्रमों के अधिकारी	6
	4
अधिकारी, आयकर	2
अधिकारी, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2
केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी	2
अधिकारी, नगर निगम	1

इन अधिकारियों के नाम प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

(ग) कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं ।

श्री धर्म सिंह रावत द्वारा कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप

2670. **श्री सोहन लाल घूसिया :**

श्री घनश्याम सिंह :

श्री शिव कुमार मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ (उ०प्र०) के एक आई०ए०एस० अधिकारी श्री धर्म सिंह रावत ने ग्राल इंडिया सेर्विसेज के कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1986 में लखनऊ और दिल्ली में भूख-हड़ताल की थी;

(ख) क्या सरकार को उन अधिकारियों के नामों की जानकारी है जिनके विरुद्ध श्री रावत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं तथा वे इस समय कौन-कौन से पदों पर तथा किन-किन स्थानों पर तैनात हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पूरा ब्यौरा प्राप्त हो गया है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) श्री डी०एस० रावत आई०ए०एस० (उत्तर प्रदेश) ने अपना स्थानान्तरण एक पद से दूसरे पद पर किए जाने के विरोध में 1986 में दिल्ली और लखनऊ में भूख हड़ताल की थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने कदाचार के लिए अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है ।

Tie-up of apple leasing and industries limited with national computing centre of U.K.

2671. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to recent advertising by Apple Leasing and Industries Ltd. claiming its tie-up with National Computing Centre of U.K.;

(b) if so, whether Government have approved the tie-up, if so, what are the terms, thereof;

(c) whether it is a fact that total amount expenditure of NCC of U.K. is about Rs. 15 crores whereas advertisements released by Apple Leasing and Industries Ltd. claimed that NCC was spending Rs. 360 crores annually on Research and Development above; and

(d) if so, what action is contemplated by Government in this regard?